



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई विल्लो, बुधवार, जुलाई 18, 1990/आषाढ़ 27, 1912

No. 298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1990/ASADHA 27, 1912

इस भाग में भिन्न दृष्टि संख्या की जाती है जिससे विधायक अलग संकाग्रह के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिकार

नई विल्लो, 18 जुलाई, 1990

मा. का. नि. 647 (अ):—गद्यपति द्वारा जारी को गई निम्न-
सिखित उद्घोषणा सर्वसामाजण के सूचनार्थ प्रकाशित को जा रही है:—

यह: मूले, भारत के राष्ट्रपति, आर. वेंकटरामन हो जम्मू व काशीर
राज्य के राज्यपाल मे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इस रिपोर्ट तथा
मूले प्राप्त इस सूचना पर विवार करने के बाद ये समाधान हो गया है
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उम्मीद राज्य का जातीय भारत
के संविधान, जैसा कि वह उम्मीद राज्य पर लागू है, (जिसे इसके
पश्चात् “राज्यान” कहा गया है) और जम्मू व काशीर के संविधान (जिसे
इसके पश्चात् “राज्य संविधान” कहा गया है) के उपर्योग के अनुसार
भी ही कलाया जा सकता है;

अतः इस मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा
उस निमित्त मूले समर्थ यन्त्रों का लाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते
हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

(अ) संविधान और राज्य संविधान के प्रतीन उक्त राज्य की सरकार
के सर्व फूर्त और उस राज्य के राज्यपाल में नियमित अधिका

उनके द्वारा प्रयोगन्वय सभी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति
के जप में स्वयं संवाचन हैं;

(ब) उद्घोषित करता है कि उक्त राज्य के विवात मंडन की
प्रक्रिया संभव द्वारा प्रदत्त उपर्योगितार के अतीत प्रशीक्षण
होती; और

(ग) निम्नलिखित आनुबंधिक और पारिणामिक उत्पाद करता है जो
इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्राप्ति बनाने के लिए मूले
प्रावधान या आठांत्र प्रतीन होते हैं; अर्थात्—

(1) पूर्वोक्त के अनुसार, इस उद्घोषणा के अण्ड (क) के
आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए फूर्तों तथा शक्तियों
का प्रयोग करने में मेरे नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के
कर में, उन सौभाग्य के जिन तरह में थोक मप्रम्, उक्त
राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करता विविष्ट होगा;

(2) संविधान के तथा राज्य संविधान के निम्नलिखित उपर्योग
के प्रतीन को एतद्वारा वितरित किया जाता है;
अर्थात्—

संविधान के अनुच्छेद 3 के पदन परन्तु का उत्तरा
भाग जिन्हें का संबंध राज्यानि द्वारा राज्य विवातमंडल

के प्रति निर्देश न है, भार उत्तर अनुच्छेद के द्वारा परालेक :

गविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उत्तर भाग जिनने का संवेद भारत के नियंत्रक श्रीर महालिलावा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के ममक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के ममक्ष रूप जानें से है ;

राज्य संविधान की धाराएँ 35 से 41 तक (जिसमें
ये दोनों सम्मिलित हैं), धारा 43 का उत्तरा भाग जिसने
भा संविध राज्य सरकार के मंत्रियों के बोच कार्य के
बढ़ावे से है, धारा 44, धारा 53 की उपधारा (1)
और उपधारा (2) का खंड (क), धाराएँ 54, 55,
56 तथा 57, धारा 58 के खंड (क) और (ग)
और उसका पहला परन्तुक, धारा 59, धारा 60, धारा
61 की उपधारा (2), जहां तक 'उत्तरा गंभीर धारा
58 के खंड (ग) और पहले परन्तुक से तथा धारा
60 से है :

धाराएँ 65, 66, 67, 71 और 72, धारा 74, 75 और 76, धारा 77 को उल्लिख (3) नाम (4), धाराएँ 85 से 98 तक (जिसमें वे दोनों गमिनियाँ हैं) और धारा 137 तक उन्हाँ भाव किसी का विवर नहीं रहित रिपोर्ट के राज्य के विधान संडर के नमस्त रखे जाने से हैं :

(3) संविधान में, और राज्य के संविधान में, राज्याल के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उन राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निरेश लाया जाएगा, और अंतिमत में तथा राज्य के संविधान में राज्य के प्रति विधान मंडल या उसके मद्दों के प्रति, द्वा लिखित, लिखे निरेश हो, जहां तक उसका संबंध उसके क्रूरों और शक्तियों से है, अर्थ, एव तक कि यार्द द्वारा अन्यथा धोकेन न हो, संतद के प्रति निरेश लाया जाएगा, और निरेश राज्य के संविधान की धारा ११ में राज्याल के प्रति और राज्य के विधान मंडल द्वारा उके प्रति तो निरेश का अर्थ कमशा राष्ट्रपति के प्रति और संतद या उसके मद्दों के प्रति निरेश लाया जाएगा;

परन्तु इनमें थी तोई बात राज्य मंत्रियान की बाया १६ को उपधारा (१), ब्रायाएं ३७ से ३१ तक (जिसमें वे दोनों अम्मिनि हैं), बाया १३२, ब्राया १४३ और दूसरी अनुसूची के विरा १ से ८ तक) जिनमें से दोनों अम्मिलित हैं) के तात्पर्य पर रावार अर्थे आलेहो और न राज्यपति को इस बंध के त्राविड (१) के अधीन, जन सेवा या जरूरि के लिए, उन राज्य के राज्यवाल के साथ-से जारी हो से दियारिय करेगी :

(1897 का 10) का उत्तर भारतीय राज्य की विधियाँ पर लागू होती हैं, ऐसे हिस्से अधिनियम या विविध के बारे में इस प्रकार प्रभावी होता हातो यह उस राज्य के विधान संडरन का अधिनियम होता ।

नई दिल्ली,
विहारी 18 जुलाई, 1990

आर. येंकटरामन
राष्ट्रीय

[फा. सं. 5/11013/4/90--सी. प्रा. अर.]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1990

G.S.R. 647 (E):—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, R. Venkataraman, President of India, have received a report from the Governor of the State of Jammu and Kashmir and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India, as applicable to that State (hereinafter referred to as "the Constitution") and of the Constitution of Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as "the State Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I:-

- (a) assume to myself as President of India all the functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the State Constitution;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for

giving effect to the objects of this proclamation, namely:—

- (i) in the exercise of the functions and powers assured to myself by virtue of clause (a) of this proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
- (ii) the operation of the following provisions of the constitution and of the State constitution, is hereby suspended, namely:—

so much of the first proviso to article 3 of the Constitution as relates to the reference by the president to the Legislature of the state and the second proviso to that article; so much of clause (2) of article 151 of the Constitution as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

sections 35 to 41 (both inclusive), so much of section 43 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State, section 44, sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 53, sections 54, 55, 56 and 57, clauses (b) and (c) of section 58 and the first proviso thereto, section 59, section 60, sub-section (2) of section 61 so far as it relates to clause (c) of, and the first proviso to section 58 and to section 60; sections 65, 66, 67, 71 and 72; sections 74, 75 and 76, sub-sections (3) and (4) of section 77, sections 85 to 88 (both inclusive) and so much of section 137 as relates to the laying of the report with a memorandum before

the Legislature of the State, of the State Constitution:

- (iii) any reference in the Constitution and the state Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference in the Constitution and the State Constitution to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and in particular, the reference in section 91 of the State Constitution to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of sub-section (1) of section 26, sections 27 to 31 (both inclusive), section 122, section 143 and paragraph 1 to 8 (both inclusive) of the Second Schedule to the State Constitution or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State:

- (iv) any reference in the Constitution or in the State Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament, by virtue of this Proclamation or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Jammu and Kashmir General Clauses Act, 1977 (Act No. XX of 1977) and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as

applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi,
The 18th July, 1990

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

[F.No. V/11013/4/90-CSR]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1990

आदेश

सा. का. नि. 648 (प्र).—एक्टराम बारा जारी किया गया नियन्त्रित आदेश संविधान की सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:—

भारत के संविधान के प्रदूषेद 356 के अधीन मेरे बारा आज जुलाई, 1990 के प्रधारहर्वे इन जारी को गई उद्दीपण के घड़ (ग) के उपलब्ध (1) के अनुसरण में, मैं एनद्वारा नियंत्रण देता हूँ कि जम्मू व कश्मीर राज्य भूकार के सभी कृत्य तथा संविधान और जम्मू व कश्मीर के संविधान के अधीन या उस गत्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके बारा प्रयोक्तव्य सभी अस्तित्व, जिनमें राष्ट्रपति ने उक्त उद्दीपण के घड़ (क) के प्रयोक्तव्य संबंध में बान लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, नियंत्रण द्वारा नियंत्रण के अधीन रखने हुए, उक्त गत्य के राज्यपाल बारा सभी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,
विनाक 18 जुलाई, 1990

धारा, वेंकटरामन,
राष्ट्रपति

[फा. मं. 5/11013/4/90—सी. एम. आर.]

नरेश चन्द्र,
गृह मंत्रिय

ORDER

New Delhi, the 18th July, 1990

G.S.R. 648 (E):—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 18th day of July 1990, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Jammu and Kashmir and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the Constitution of Jammu and Kashmir or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi,
The 18th July, 1990.

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

[F.No. V/11013/4/90-CSR]
(NARESH CHANDRA)

Home Secy.